भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 610

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

.....

येत्तिनाहोले लिफ्ट सिंचाई परियोजना

610. **श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:**

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) येत्तिनाहोले लिफ्ट सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है जिसका उद्देश्य पश्चिमी घाटों के अतिरिक्त जल को कर्नाटक के सूखा प्रवण और अनियमित वर्षा वाले जिलों जैसे चिक्कबल्लापुर, कोलार, बैंगलोर ग्रामीण, तुमकूर रामनगर में पेयजल उपलब्ध कराने और इन क्षेत्रों में टैंकों को भरने के लिए विपथित करने का है;

(ख) सरकार द्वारा कई वर्षों पहले अनुमोदित किए जाने के बाद भी उक्त परियोजना में विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना के कुल परिव्यय का ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(घ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडु)

(क): येत्तिनाहोले लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक राज्य परियोजना है जो कर्नाटक राज्य द्वारा वित्तपोषित और निष्पादित की जाती है। यह परियोजना 17.02.2014 को कर्नाटक सरकार द्वारा 12912.36 करोड़ रू. की लागत से अनुमोदित की गई। इस लक्ष्य चिक्काबालापुर, कोलार, चिक्कामागालुरू, हासन्न, तुमकूर, रामानगर और बेंगलूरू ग्रामीण के सात (7) सूखे प्रभावित जिलों के 29 ताल्लुकों में 6557 गांवों और 38 कस्बों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर बहने वाली स्ट्रीम से 24.01 टीएमसी अधिशेष जल को मोड़ना है। इस परियोजना में इसी का 15.029 टीएमसी जल उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त,

इससे पांच (5) जिलों चिक्काबालापुर, कोलार, हासन्न, तुमकूर और बैंगलोर ग्रामीण) के 527 सूक्ष्म सिंचाई टैंकों को भरण के लिए 8.967 टीएमसी जल उपयोग किया जाएगा।

यह परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का चरण-I लिफ्ट घटकों से संबंधित है और यह जल्द पूरी हो जाएगा। परियोजना के चरण -II के तहत, टी.जी हाल्ली, रामानगर, मधुगिरी और गोरीबिंदनुर के बायरागोंडलू जलाशय और फीडर कैनल का कार्य प्रगति पर हैं। कुंडना लिफ्ट, कोलार और श्रीनिवासपुर फीडरों का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

(ख): कर्नाटक सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भूमि अधिग्रहण में समय, केपीटीएसएल, एनएचएआई, रेलवे, जीएआईएल जैसे दूसरे विभागों से स्वीकृति में देरी, वन विभाग और कोविड-19 महामारी के कारण विलम्ब हुआ है।

(ग): 12912.36 करोड़ रू. के शुरूआती अनुमानित लागत में से अभी तक 9006.27 करोड़ रू. का व्यय किया गया है (भूमि अधिग्रहण लागत सहित)

(घ): संपूर्ण परियोजना दिसंबर, 2023 तक पूरी की जाने की योजना है।

*****